

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 51/25

GCMS NO 2025/78

हनुमान सहाय पुत्र उमराव सिंह जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांत

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र हनुमान सहाय
2. सुगरवती पत्नि हनुमान सहाय
3. गोरधनी पत्नि हरज्ञान
4. शिवराम सिंह पुत्र गयाजीत सिंह समस्त जातियान गुर्जर निवासी बाढमहासिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली
6. उप पंजीयक टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 25/24 निर्णय दिनांक 22.8.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनिल कुमार जिंदल

अभिभाषक रेस्पो0 श्री हंसराम गुर्जर

दिनांक 27.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.8.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बाढमहासिहपुरा की आराजी खसरा न0 111/391 रकबा 0.04, 112 रकबा 0.30, 124 रकबा 1.56, 466 रकबा 0.29, 467 रकबा 0.01, 468 रकबा 0.58, 469 रकबा 0.57 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.01 है0 मे गैरसायलान न 0 1 सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखील है। खसरा न0 465 रकबा 0.5, 545 रकबा 0.10, 557 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है0, मे गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/2 का, गैरसायल संख्या 2 हिस्सा 1/8 का, गैरसायल न0 3 हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान न0 1 के बुजुर्गों से विरासत मे मिली है। सायलान गैरसायल न0 1 का पुत्र है। जिनको वाईबर्थ अपने पिता गैरसायल न0 1 की आराजी मे नोशनल हिस्से के अधिकार है तथा अपने नोशनल हिस्सा 1/3 हिस्से की खातेदारी अपने हक मे कराने का अधिकारी है। इसी प्रकार सायला न0 2 गैरसायल न0 1 की पत्नि है। जिसको अपने पति का विरासत मे मिली आराजी मे हिस्सा 1/3 की खातेदारी अपने हक मे कराने का कानूनी अधिकार है। गैरसायल न0 1 गलत संगत मे है नशा पता करता है। आये दिन अपने नाम दर्ज


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमि में से सायलान के हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देता रहता है। दिनांक 20.5.24 को सायलान अपने हिस्से की आराजी में आगामी फसल के लिए सूल बबूल साफ कर रहे थे कि गैरसायल न0 1 आया और कहा कि तुम इस आराजी पर आना छोड़ दो इस आराजी की खातेदारी मेरे नाम है। मैं इस आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करूंगा। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम बाढमहासिहपुरा की आराजीयात खसरा न0 111/391 रकबा 0.04, 112 रकबा 0.30, 124 रकबा 1.56, 466 रकबा 0.29, 467 रकबा 0.01, 468 रकबा 0.58, 469 रकबा 0.57 है0, 465 रकबा 0.55, 545 रकबा 0.10, 557 रकबा 0.25 है0 को रहन बय नहीं करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ सायलान/रेस्प0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायल न0 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


अपील पेश होने पर 'दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में गैरसायल/अपीलांट की तामिल नहीं होने के बावजूद भी तामिल मानकर एकतरफा कार्यवाही की गई। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 21.6.24 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्मन तामिल नहीं आये, ना ही गैरसायल न0 1 व 2 द्वारा नोटिस रजिस्ट्री की रसीद में ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की, केवल दावे में प्रस्तुत नोटिसों पर परिवारजनो की तामिल मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि मूल वाद के सम्मन पर अपीलांट हनुमान सहाय की तामिल पर तामिल कुन्नदा द्वारा हनुमान सहाय के नोटिस पर गोर्धनी नाम की पत्नि को नोटिस देना बताया है। जबकि अपीलांट की पत्नि का नाम गोर्धनी नहीं है बल्कि सुगरवती है। जो रेस्प0 न0 2 है तथा गोर्धनी मूलवाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में गैरसायल न0 2 है जो हरज्ञान की पत्नि है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को नहीं देखकर तामिल को सही मानकर कानूनी भूल की है और अपीलांट की तामिल को अपीलांट की पत्नि (परिजन) मानकर विधि विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी। जबकि अपीलांट को उक्त मुकदमे की जानकारी नहीं होने दी तथा अदालत मातहत अपनी आदेशिका दिनांक 21.6.24 में परोकार सरकार की उपस्थिति मानते हुए जबाब का मौका दिये बिना दिनांक 21.6.24 को पत्रावली बहस में विधि विरुद्ध नियत कर दी गई। जो विधि विरुद्ध है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि अपीलांट गलत संगति में रहा हो या अपीलांट किसी प्रकार नशा करता हो ऐसी कोई भी साक्ष्य रेस्पोंडेंट नं० 1 व 2 द्वारा पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य या पड़ोसिया के अन्य व्यक्ति का शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि अपीलांट को नशे व गलत संगति रखता हो इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 अपीलांट के जीवनकाल में अपीलांट की जमीन को हड़पना चाहते हैं और रेस्पोंडेंट नं० 2 जो अपीलांट की पत्नी है अपीलांट के साथ पिछले 25 वर्षों से नहीं रह रही है बल्कि रेस्पोंडेंट नं० 1 को बहका कर यह मुकदमा प्रस्तुत करवा दिया है। उक्त तथ्य की जाँच किये बिना ही अदालत मातहत द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित करने में भारी तथ्यात्मक व कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेंट नं० 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है तथा अपीलांट खातेदार है तथा ना ही रेस्पोंडेंट नं० 1 व 2 द्वारा अपना कब्जा साबित किया है। उक्त तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नहीं कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोंडेंट नं० 1 व 2 द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें कानूनन प्रोपर प्रतिवादीगणों की तामिल होना आवश्यक है। जबकि अपीलांटगण को अदालत मातहत का मुकदमे की सूचना नहीं मिली, ना ही प्रोपर सम्मनों की तामिल हुई। इसलिए भी अदालत मातहत द्वारा एक तरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने में भारी भूल एवं तथ्यात्मक भूल की है। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी दिनांक 22.4.25 को हुई जब रेस्पोंडेंट नं० 1 व 2 द्वारा अपीलांट को धमकी दी कि रेस्पोंडेंट नं० 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय में मुकदमा पर अपीलांट की फर्जी तामिल करवा कर बिना सूचना दिये ही एक तरफा में स्थगन आदेश जारी करवा लिया जिस पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की तरफ से दिनांक 25.25 को को मुकदमे की जानकारी कर निर्णय की नकल लेने बाबत दिनांक 25.25 को आवेदन किया तथा दिनांक 5.5.25 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट के विरुद्ध फर्जी तामिल होने व मुकदमे में एक पक्षीय निर्णय की जानकारी हुई। चूंकि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी इसलिए अपीलांट उक्त निर्णय की अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.8.24 अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट ने अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अपीलांटगण की तामिल नहीं हुई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सम्मन अपीलांटगण को तलब किया गया है। अपीलांटगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं साथ अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावे में अपीलांटगण की तामिल होने


राजस्य अपील प्राधिकारी
सवाई मधोपुर

के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटगण की विधिवत तामिल मानी है। जब अपीलाटगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही प्रकरण को बहस में नियत किया गया है। इस प्रकार अपीलाट का उक्त कथन मिथ्या है। जहाँ तक अपीलाट के गलत संगत में होने के संबंध में साक्ष्य का प्रश्न है तो वह विनिश्चय दावे में तय होगा हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें केवल प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं प्रईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना होता है। उक्त तीनों बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पों के पक्ष में बखूबी साबित माने हैं। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत हक एवं अधिकारों का निर्धारण दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेंगे। पक्षकारों के मध्य वाद बाहुलता नहीं बढ़े एवं भूमि वादग्रस्त किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं हो इस विधिक तथ्य को देखते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाई रखे जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलाट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पों का कब्जा काश्त नहीं है जबकि सत्यता यह है कि रेस्पों का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलाट/गैरसायल न० 1 को विरासत में प्राप्त हुई है इस कारण उक्त आराजीयात में सायलान/रेस्पों नोशनल शेयर प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलाट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाट की कोई तामिल नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सीपीसी के प्रावधानों के तहत गैरसायलान अर्थात् अपीलाटगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये हैं। इससे जाहिर है कि अपीलाटगण की विधिवत तामिल हुई है। अपीलाटगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। इसी प्रकार अपीलाट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पों का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात के हक एवं अधिकारों का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेंगे। क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात अपीलाट/गैरसायल न० 1 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा रेस्पों एवं अपीलाट आपस में पिता पुत्र एवं पति पत्नि है। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया जाना होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु सायलान/रेस्पों के पक्ष में साबित माना है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत पक्षकारों के मध्य वाद बाहुलता नहीं हो तथा भूमि किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं हो इस विधिक तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नहीं आने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांत की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 25/24 में पारित निर्णय दिनांक 22.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर